सेमीकंडक्टर हब बनेगा भारत

- 200 स्टार्टअप होंगे प्रोत्साहित
- 12 परियोजनाओं से बढ़ेगा विनिर्माण का दायरा

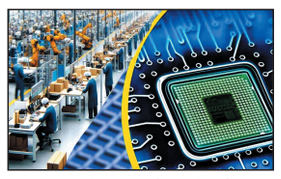

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 18 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरूवार को वैश्विक चिप विनिर्माण के लिए भरोसेमंद गंतव्य के रूप में पेश करते हुए कहा कि सरकार अनुकूल नीतियों और रूपरेखाओं के जरिये उद्योग की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठा रही है.

'सेमीकॉन इंडिया 2026' के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर परिवेश तेजी से बढ़ रहा है जिससे नवाचार, निवेश और वृद्धि के नए अवसर खुल रहे हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया को चिप विनिर्माण के लिए नए और भरोसेमंद ठिकानों की जरूरत है और भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को भारत इसके लिए खुद को तैयार कर रहा है. भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में सभी कदम उठा रहा है. पीएम ने कहा कि अब तक चिप विनिर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है और अगले चरण में इनकी संख्या और बढ़ेगी. 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' का परिव्यय पहले चरण के 8 अरब डॉलर से बढ़ाकर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है. मोदी ने कहा चाहे नीतियां हों, नियामकीय रूपरेखा हो, आपकी सफलता के लिए जो भी जरूरी है, उसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी प्रयास कर रही है. उन्होंने पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर और जापान की रेटिंग एजेंसी जेसीआरए द्वारा भारत की रेटिंग बढ़ाए जानेचिप डिजाइन पर जोर, 200 स्टार्टअप व कंपनियों को बढ़ावाकेंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार देश के सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण सेमीकॉन 2.0 के तहत भारत में चिप डिजाइन करने वाले कम से कम 200 स्टार्टअप और कंपनियों को बढ़ावा देगी.

> 'सेमीकॉन इंडिया 2026' के उद्?घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन सेमीकॉन 2.0 के छह स्तंभों में पहला होगा. उन्होंने बताया कि मिशन के पिछले चरण में 105 से अधिक स्टार्टअप ने चिप डिजाइन के क्षेत्र में प्रयास किया था, जिनमें से करीब 20 को लगभग 800 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी मिली थी. वह महज शुरुआत थी. इस बार हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है. हम सेमीकंडक्टर की जरूरतों के पूरे दायरे में भारत में चिप डिजाइन करने वाले कम से कम 200 स्टार्टअप और कंपनियों को लक्ष्य बनाएंगे.

सोलर प्लांट के लिए एसबीआई देगा 50 करोड़ रुपए तक लोन

- कैप्टिव प्रोजेक्ट में 10 करोड़ तक की ऋण सुविधा
- 20 से 25 फीसदी राशि ग्राहक को लगानी होगी

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 18 सितंबर. सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कारोबारियों, एमएसएमई और सहकारी हाउसिंग सोसाइटी के लिए 'सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस' योजना शुरू की है.

इसके तहत छत या जमीन पर ग्रिड से जुड़े सोलर पावर सिस्टम लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है. योजना में परियोजना के प्रकार के आधार पर 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक के ऋण का प्रावधान बताया गया है.

कैप्टिव सोलर परियोजनाओं के लिए एमएसएमई, कारोबारी संस्थाओं और सहकारी हाउसिंग सोसाइटी को अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन मिल सकता है. इसमें ग्राहक को परियोजना लागत का कम से कम 20 फीसदी हिस्सा खुद लगाना होगा. ऋण चुकाने के लिए अधिकतम 10 साल तक की अवधि मिल सकती है.

पीएफ पेंशन में 67% तक बढ़ोतरी

- बीमा कवर 7 से बढ़कर 10 .50 लाख
- वेज सीलिंग बढ़ने से बढ़ेगा लाभ

नवभारत न्यूज नेटवर्क.

नई दिल्ली,18 सितंबर सरकार ने ईपीएफ वेज सीलिंग की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है.

इस फैसले से न सिर्फ आपकी सेविंग्स और पेंशन में इजाफा होगा, बल्कि कर्मचारियों को मिलने वाला एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम कवर भी 7 लाख रुपये से बढ़कर 10.50 लाख रुपये या उससे अधिक हो सकता है. हालांकि इसकी अंतिम पुष्टि सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही होगी. मौजूदा वेतन सीमा के तहत ईपीएफ खाताधारकों को 7.50 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है. चूंकि इंडीएलआई इंश्योरेंस की रकम 15,000 रुपये की सैलरी लिमिट के हिसाब से तय होती है, इसलिए इस लिमिट को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने से ईडीएलआई के तहत मिलने वाला इंश्योरेंस कवर काफी बढ़ सकता है. मौजूदा ईडीएलआई नियमों के मुताबिक, नौकरी के दौरान किसी ईपीएफ मेंबर की मौत होने पर उसके नॉमिनी को कम से कम 2.5 लाख रुपये और ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रुपये इंश्योरेंस के रूप में मिलते है.

> अब ईपीएफ वेज सीलिंग 25,000 रुपये हो गई है तो अधिकतम बीमा राशि बढ़कर 10.50 लाख रुपये या उससे भी ज्यादा हो सकती है. ईवाई इंडिया में पीपल अडवाइजरी सर्विसेज टैक्स के पार्टनर पुनीत गुप्ता ने बताया कि सैलरी लिमिट बढ़ने से कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स (बचत) और सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ने की उम्मीद है. इंडीएलआई 2026 स्कीम के नोटिफिकेशन के मुताबिक, ईडीएलआई कैलकुलेशन के लिए ईपीएफ सीलिंग 1,75,000 रुपये है.

त्योहार से पहले पनीर पर फूड सेफ्टी का शिकंजा

- देशभर में एनालॉग पनीर पर लग सकता है बैन
- वनस्पति तेल, स्टार्च से तैयार होता है एनालॉग

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली,18 सितंबर अगर आप भी बाजार या किसी रेस्टोरेंट में खाने के दौरान पनीर की डिश बड़े चाव से खाते हैं तो यह जानकारी आपके लिए अहम है.

त्योहारी सीजन से पहले असली दूध से बने पनीर की जगह बाजार में मिलने वाले सस्ते पनीर यानी एनालॉग पनीर को लेकर अब फूड सेफ्टी अथॉरिटी सख्त रुख अपना रही है. हालांकि कई राज्यों में पहले ही इस तरह के पनीर पर कार्रवाई की जा चुकी है और अब इसे देश भर में बैन करने की तैयारी की जा रही है. एनालॉग पनीर को लेकर कई राज्यों में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है. छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक समेत कई राज्यों में एनालॉग पनीर को लेकर कार्रवाई हुई है. एफएसएसएआई के मुताबिक अभी पूरे देश में एनालॉग पनीर पर बैन लागू नहीं हुआ है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ राजित पुन्हानी ने बताया कि 24 सितंबर को सभी राज्यों के साथ बैठक की जाएगी.

रुपे कार्ड को बढ़ावा देगी सरकार

नई दिल्ली. यूपीआई पर टैक्स के बीच सरकार ने रुपे कार्ड को बढ़ावा देने का निश्चय किया है जिससे बाजार में मौजूद अमेरिकी मास्टर कार्ड सहित अन्य विदेशी क्रेडिट कार्ड को स्वदेशी रुपे कार्ड से चुनौती दी जा सके, सरकार का मानना है कि इससे उसे 2 लाभ होंगे. एक, रुपे कार्ड को नया बाजार मिलेगा. दूसरा, कांग्रेस सहित विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि विदेशी कार्ड को लाभ देने के लिए यूपीआई पर टैक्स लगाया जा रहा है. उस आरोप से भी सरकार को निपटने में सफलता मिलेगी. देश के क्रेडिट कार्ड बाजार में इस समय मास्टर कार्ड, वीसा और अमेरिकन एक्सप्रेस का बोलबाला है. यह बाजार के 62 से 80 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा रखते हैं.

सेकर को विश्व तमिल गौरव सम्मान

- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान
- कार्यक्रम में 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों ने लिया भाग

नवभारत कनेक्ट

वेल्लोर,18 सितंबर वीआईटी के वाइस-प्रेसिडेंट डॉ. सेकर विश्वनाथन को मॉरीशस में आयोजित 'वर्ल्ड तमिल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस' में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनके बेहतरीन योगदान के लिए प्रतिष्ठित 'क्राउन ज्वेल ऑफ वर्ल्ड तमिल' (उलगा तमिलर मामनी) पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

'ग्लोबल तमिल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस' और 'ग्लोबल इकोनॉमिक समिट' का 13वां संस्करण मॉरीशस में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित किया गया. कार्यक्रम में 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों, सरकारी मंत्रियों, आर्थिक विशेषज्ञों और निवेशकों सहित 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय निवेश, नए व्यावसायिक संबंधों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय सेवाओं, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्टार्टअप और वैश्विक व्यापार जैसे विषयों पर चर्चा हुई. कार्यक्रम में शामिल होने वाले गणमान्य व्यक्तियों में वीआईटी के चांसलर डॉ. जी. विश्वनाथन, स्कूली शिक्षा मंत्री राजमोहन और मद्रास डेवलपमेंट सोसाइटी व वर्ल्ड तमिल इकोनॉमिक फाउंडेशन के अध्यक्ष वी.आर.एस. संपत शामिल थे. मॉरीशस के राष्ट्रपति धर्मबीर गोखूल ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार प्रदान किए.

फास्टैग बैंक बदलने पर 6 महीने की पाबंदी

नई दिल्ली, 18 सितंबर. फास्टैग इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों के लिए बैंक बदलने की सुविधा तो शुरू हो गई है, लेकिन इसमें भी एक सीमा तय की गई है. अब फास्टैग को एक बैंक से दूसरे बैंक में पोर्ट कराने के बाद तुरंत दोबारा बैंक नहीं बदला जा सकेगा. इसके लिए वाहन मालिकों को 6 महीने यानी 180 दिन का इंतजार करना होगा. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने फास्टैग पोर्ट की सुविधा के लिए राजमार्ग यात्रा ऐप में वनटैग सुविधा शुरू की है. इसके जरिए वाहन चालक अपने मौजूदा फास्टैग को बिना बदले बैंक और वॉलेट की जानकारी बदल सकते हैं. यानी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगा फास्टैग स्टिकर हटाने या नया लगाने की जरूरत नहीं होगी.

सोच को एनएसई में 25 गुना रिटर्न की उम्मीद

फंड एनएसई के आईपीओ में अपनी दस साल पुरानी हिस्सेदारी का 20% बेचेगा

नवभारत कनेक्ट

मुंबई, 18 सितंबर सोच ग्लोबल स्ट्रैटेजिक होल्डिंग्स लिमिटेड, मॉरिशस (जो सोच ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड की पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी है और जिसे साथ में 'सोच ग्लोबल' कहा जाता है), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में अपने दस साल पुराने इन्वेस्टमेंट से आंशिक रूप से बाहर निकल रही है.

फंड एनएसई के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ में 'ऑफ़र फ़ॉर सेल' के ज़रिए हिस्सेदारी बेच रहा है, जो आज खुला है. फंड ने जनवरी 2016 में इंडस्ट्रियल फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड से 3,950 प्रति शेयर की कीमत पर 1,50,000 एनएसई इक्विटी शेयर खरीदे थे, जिनकी कुल कीमत 59.25 करोड़ थी. अगले दशक में, बिना किसी अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट के, कॉर्पोरेट एक्शन के ज़रिए यह होल्डिंग बढ़कर 82,50,000 शेयर हो गई. इन कॉर्पोरेट एक्शन को ध्यान में रखते हुए, फंड की औसत खरीद लागत 71.8 प्रति शेयर है. फंड अब 16,50,000 इक्विटी शेयर बेच रहा है, जो उसकी होल्डिंग का 20% है. यह बिक्री के 1,700 से 1,785 प्रति शेयर के प्राइस बैंड पर हो रही है, जिससे बिक्री की कुल कीमत लगभग 280 से 295 करोड़ बैठती है.

मूडीज ने जीडीपी अनुमान बढ़ाया

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नयी दिल्ली, 18 सितंबर वैश्विक साख निर्धारक एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि का अनुमान छह प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया है.

मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. उसने उम्मीद जताई कि दूसरी जी20 अर्थव्यवस्थाओं और समान साख वाले उभरते बाजारों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ता रहेगा. हालांकि, उसने चेतावनी दी कि ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से अर्थव्यवस्था की गति अनुमान से कम रह सकती है. उसका कहना कि ईंधन की लागत लंबे समय तक ऊंची बनी रही तो महंगाई और घरेलू खपत पर दबाव पड़ सकता है. इससे सकल आर्थिक विकास पर भी असर पड़ सकता है.

भारत बनेगा डेवलपर्स की दुनिया का केंद्र

- 2030 तक सबसे बड़ा डेवलपर समुदाय बनने का दावा
- टेक दिग्गजों ने साझेदारी बढ़ाने पर की चर्चा

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली,18 सितंबर. माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने भारत की तकनीकी क्षमता और ह्यूमन कैपिटल की सराहना करते हुए कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर समुदाय बन सकता है.

उन्होंने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षमता को मजबूत करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिबद्धता दोहराई. सिएटल में भारत के कॉन्सुलेट जनरल की ओर से आयोजित 'आईडियाज4इंडिया: इंडियन अमेरिकन टेक सीईओ फोरम-अनलॉकिंग द टेक डिविडेंड' कार्यक्रम में नडेला ने भारत-अमेरिका तकनीकी साझेदारी पर विचार रखे. यह आयोजन 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के बाद किया गया था, जिसमें भारतीय-अमेरिकी टेक समुदाय की विशेषज्ञता और अनुभवों को साझा किया गया.

कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, बोइंग, ओपनएआई, एंथ्रोपिक और इंटेल जैसी कंपनियों से जुड़े 40 से अधिक भारतीय मूल के सीईओ और सीटीओ शामिल हुए.

समाचार विशेष

महाराष्ट्र में बदलेगा एनसीपी का स्लोगन

- पीके की सलाह पर सुनेत्रा पवार की बड़ी रीलांचिंग की तैयारी

मुंबई. अजित पवार की प्लेन हादसे में मौत के बाद कमजोर पड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) महाराष्ट्र में अपने संगठन को मजबूत करने की योजना पर काम कर रही है. राष्ट्रवादी कांग्रेस में अब एकच वादा, अजित दादा की जगह वहिनी (भाभी) हैं ना के नारे के साथ डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार पार्टी की मुख्य चेहरा बनेंगी.

नई योजना के तहत सुनेत्रा की रा'य भर में सक्रियता बढ़ाई जाएगी. एकच वादा, अजित दादा नारा लंबे समय तक अजीत पवार के समर्थकों की पहचान रहा है. सूत्रों की मानें तो जनसुराज के संस्थापक और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह पर एनसीपी के मेकओवर की तैयारी कर ली है. सूत्रों की मानें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम नासिक में 27 सितंबर को रखा गया है. इस कार्यक्रम में पार्टी नए नारे के साथ सामने आएगी. 2019 में बारामती में देवेंद्र फडणवीस की सभा के दौरान भी राकां कार्यकर्ताओं ने यह नारा लगाया था. सालों तक ये नारा अजित गुट की प्रमुख राजनीतिक पहचान बन गया. अब सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में पार्टी को नई पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है. इसी क्रम में वहिनी हैं ना! का नए स्लोगन दिया गया है.

पर्दे के पीछे हैं प्रशांत किशोर: राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) की सलाह के आधार पर सुनेत्रा पवार की राजनीतिक सक्रियता और संगठन को मजबूत करने की योजना पर काम हो रहा है.

नई पीढ़ी पर लाया जाएगा आगे

सूत्रों के अनुसार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने नई पीढ़ी को आगे लाने की योजना बनाई है. 27 सितंबर को नाशिक में एक दिवसीय रा'यव्यापी अधिवेशन में सुनेत्रा पवार की औपचारिक रिलॉन्चिंग होगी. इसमें करीब 700 से 750 नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे. पार्टी संगठन में नए चेहरों को आगे ला सकती है. सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ पवार पूरी रणनीति को तय कर रहे हैं. हालांकि प्रफुल्ल पटेल के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष पद और सुनील तटकरे की प्रदेशाध्यक्ष जिम्मेदारी को लेकर भी पार्टी में असमंजस बना हुआ है. सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली एनसीपी महाराष्ट्र सरकार में दूसरी सबसे बड़ी घटक है. पार्टी केंद्र में पीएम मोदी की सरकार को समर्थन दे रही है.

भजनलाल के गृह जिले में कुर्सी का खेल पलटा

भरतपुर मेयर के लिए भाजपा के सामने निर्दलीय की चुनौती, कांग्रेस कहां?

जयपुर. सीएम भजनलाल के गृह जिले भरतपुर नगर निगम में मेयर की कुर्सी के लिए सियासी मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है. भाजपा के सामने निर्दलीयों ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और इस दांव के केंद्र में हैं विचित्रा सिंह.

वार्ड 17 से निर्दलीय पार्षद चुनी गईं विचित्रा सिंह ने बुधवार को मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया. विचित्रा सिंह की उम्मीदवारी इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि वह भरतपुर के पूर्व मेयर शिव सिंह भोंट की पत्नी हैं. भोंट खुद इस बार वार्ड 19 से निर्दलीय चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पत्नी की जीत के बाद मेयर पद की दौड़ में एंट्री ने भरतपुर की स्थानीय राजनीति में नए समीकरण खड़े कर दिए हैं. अब मुकाबला भाजपा की अनुराधा सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार विचित्रा सिंह के बीच है.

कौन हैं विचित्रा सिंह : विचित्रा सिंह ने वार्ड 17 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता है. चुनाव के बाद निर्दलीय पार्षदों के बीच बने समीकरण में उन्हें मेयर पद के लिए आगे किया गया. उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनका पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड है. उनके पति शिव सिंह भोंट भरतपुर के पूर्व मेयर रह चुके हैं और नगर निकाय की राजनीति में सक्रिय रहे हैं. यानी विचित्रा सिंह भले ही पहली बार मेयर पद की दौड़ में उतरी हों, लेकिन उनके पीछे निकाय राजनीति का अनुभव रखने वाला परिवार है.

शिव सिंह भोंट का पुराना राजनीतिक कनेक्शन

शिव सिंह भोंट 2014 में भाजपा के टिकट पर भरतपुर के मेयर रह चुके हैं. इसके बाद भी उनकी सक्रियता स्थानीय राजनीति में बनी रही. इस बार हालांकि उन्होंने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल नहीं कर सके. लेकिन पत्नी विचित्रा सिंह की जीत के बाद वह फिर भरतपुर की मेयर की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं. भोंट ने अपनी पत्नी के समर्थन में अलग-अलग दलों के पार्षदों के साथ संपर्क होने का दावा किया है.

पंजाब में पायलट को बड़ी चुनौती

चंडीगढ़. सवाल है कि क्या सचिन पायलट को पंजाब में कामयाबी मिलेगी? ध्यान पहे 2018 में जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती थी तब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे और सब मानते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की थी. हालांकि वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे. उसके बाद कुछ विवादों की वजह से वे राजनीति में थोड़ा बैकफुट पर रहे. कुछ समय पहले राष्ट्रीय संगठन में आए हैं तो उसके बाद उनकी पहली बड़ी परीक्षा पंजाब में होने वाली है. वहां के प्रभारी भूपेश बघेल को हटा कर असम भेजा गया है. माना जा रहा है कि बघेल की जोर जबरदस्ती वाली राजनीति के चलते रा'य में कांग्रेस की गुटबाजी और बढ़ गई थी. बहरहाल, पायलट के प्रभारी बनने के बाद संयोग ऐसा रहा कि कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया. एक किसान गुमनाम सिंह ने पिछले दिनों यह कहते हुए खुदकुशी कर ली कि उसका बेटा नशे की गिरफ्त में है और उसने राज्य सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से इसकी शिकायत की तो उसे प्रताड़ित और अपमानित किया गया.

निर्देश | हैदराबाद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित

दक्षिणी राज्यों के कृषि रोडमैप पर मंथन

नवभारत कनेक्ट

हैदराबाद/नई दिल्ली, 18 सितंबर 2026, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिणी राज्यों की रीजनल कृषि कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यों को कृषि क्षेत्र में तय किए गए लक्ष्यों और कमिटमेंट को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि दिनभर में जिन विषयों पर चर्चा हुई है, उसमें से जो एक्शनएबल पॉइंट्स हैं, उन पर राज्यों को गंभीरता से काम करना होगा. केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर एक एग्रीकल्चर टीम हैं. हमारे साइंटिस्ट, हमारे किसान, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, भारत की एक टीम एग्रीकल्चर है. हम मिलकर काम करें. उन्होंने कहा कि इस कांफ्रेंस में राज्यों ने जो कमिटमेंट दिए हैं, उन्हें पूरा करना होगा. नहीं तो ये एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर किसी राज्य ने फार्मर आईडी का काम दिसंबर तक पूरा करने का कमिटमेंट किया है तो उसे दिसंबर तक पूरा करना होगा. अलग-अलग कामों को दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन पर कार्रवाई जरूरी है.

सिर्फ ईटिंग, मीटिंग, सीटिंग नहीं, परिणाम देना है: केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर कांफ्रेंस के बाद तय किए गए काम नहीं हुए तो पूरी कवायद बेकार हो जाएगी. एक दिन हम आए, ईटिंग, मीटिंग, सीटिंग कर ली. और कुछ नहीं किया तो ये चीटिंग हो जाएगी जनता के साथ. ये हमको नहीं करना है, हमको परिणाम देना है. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि ऊपर बैठी हुई टीम, कृषि मंत्री और नीचे काम करने वाली टीम मिलकर काम करेगी.

फार्मर आईडी और एग्री स्टैक पर तेजी से काम करें राज्य

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एग्री स्टैक कितना महत्वपूर्ण है, यह सभी राज्यों ने समझा होगा. फार्मर आईडी बनाने के काम में काफी प्रगति हुई है. तेलंगाना और कर्नाटक 75 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गए हैं. वहीं तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में जियो रिफरेंसिंग का काम भी अच्छा हुआ है. उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल ने पूर्णता हासिल की है. लेकिन जहां फार्मर आईडी बनाने में अभी और मेहनत की जरूरत है, उनमें केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं. उन्होंने कहा कि निश्चित समय सीमा के भीतर फार्मर आईडी का काम पूरा करना जरूरी है.